

सम्पादकीय

आरएलडी ने पलटी मारने के संकेत देकर उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की रीढ़ तोड़ दी है

आरएलडी के एक बड़े नेता ने जानकारी दी कि आरएलडी और बाजपी का गठबंधन लगभग तय हो गया है। चार से पांच सीटें हर हाल में बीजेपी आरएलडी को दे रही है। हालांकि हमारी सात सीटों की मांग है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की मीटिंग भाजपा नेताओं के साथ जारी है। उत्तर प्रदेश में सियासत का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। यूपी का हाल यह है कि यहां बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी की बिछुई बिसात में फंसते जा रहे हैं। हालत यह है कि चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस और बसपा चुनावी मैदान से नदरद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जमीनी हकीकत से दूर तंज कसने की राजनीति तक सिमट कर रह गये हैं। इंडी गठबंधन में दरार ही दरार नजर आ रही है। इसीलिए तो राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के नेता जयंत चौधरी भी इंडी से किनारा करते नजर आ रहे हैं। रालोद के विश्वास का हाल यह है कि उन्हें समझाते के तहत सपा से मिली सात सीटों की जगह बीजेपी से मिलने वाली चार सीटें ज्यादा लुभा रही हैं। हालांकि जयंत चौधरी और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, परंतु दोनों दलों ने इन खबरों का खंडन भी नहीं किया है। हां, समाजवादी पार्टी जरूर सफाई दे रही है कि उसके और रालोद का गठबंधन अटूट है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को ऑफर की हैं। इनमें कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक दल इंडी गठबंधन के उन 28 दलों में शामिल था जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तैयार था, लेकिन चुनाव की घोषणा भी नहीं हो पाई कि उससे पहले ही आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने पलटी मार दी। उत्तर प्रदेश में साल 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाला राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से भी नाता तोड़ सकता है। आरएलडी के एक बड़े नेता ने जानकारी दी कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय हो गया है। चार से पांच सीटें हर हाल में बीजेपी आरएलडी को दे रही है। हालांकि हमारी सात सीटों की मांग है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की मीटिंग भाजपा नेताओं के साथ जारी है। इस संबंध में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी बहुत पढ़े-लिखे नेता है। वह प्रदेश की खुशहाली और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के साथ नहीं जायेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह बताया और कहा कि सपा-रालोद का संबंध अटूट है। कुल मिलकर एक ओर प्रदेश में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, वहीं इंडी गठबंधन करीब-करीब पूरी तरह से बिखर गया है। कहने को तो पिछले दो साल से उपरोक्त बातें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं।

फलाहाल सपा आर कांग्रेस साथ खड़ नजर आ रहा है, जब तक कांग्रेस सीटों के लिए मुंह नहीं खोल रही है। सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों का आफर दिया है। यदि रालोद इंडी से अलग हो जाता है तो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को एक-दो सीटें और मिल सकती हैं। मगर इतनी सीटों पर भी जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस ने यूपी में अभी तक चुनाव की तैयारी ही नहीं शुरू की है। यूपी में इंडी गठबंधन क्यों बिखर रहा है, इसकी तह में जाया जाये तो सबसे बड़ा कस्तूरवार चेहरा राहुल गांधी ही नजर आते हैं। वैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भूमिका भी सार्थक नजर नहीं आ रही है। अखिलेश जिस तरह से बसपा को इंडी गठबंधन से दूर रखने के लिए अड़ गये, वह भी किसी तरह से सही नहीं था। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। यूपी में कभी कांग्रेस की तूती बोला करती थी, यूपी के सहारे ही कांग्रेस केन्द्र की सत्ता पर काबिज होती थी। यूपी गांधी परिवार का चुनावी गढ़ हुआ करता था। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर जैसे जिलों में तो कांग्रेस को कोई टक्कर भी नहीं दे पाता था, लेकिन अब सब बदल चुका है। कांग्रेस के रणनीतिकार और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी यूपी छोड़कर जा चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से मिली कपरी हार के बाद से राहुल ने मुड़कर यूपी की तरफ नहीं देखा। प्रियंका गांधी ने साल 2018 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले उन्होंने सिफ़र अमेठी और रायबरेली तक ही खुद को सीमित रखा हुआ था। जनवरी 2019 में उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया। लेकिन पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद प्रियंका गांधी को सितंबर 2020 में पूरे राज्य का प्रभारी बना दिया गया था। पूरी तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रियंका गांधी पार्टी का आक्रामक चेहरा बनकर उभरी। वह लखीमुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से टक्कराकर जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिलीं। उन्होंने राज्य की योगी अदित्यनाथ सरकार पर भी निशाने साधे। उस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू को प्रियंका गांधी की पसंद के तौर पर देखा जाने लाया। लेकिन प्रियंका गांधी का साल 2022 में लड़की हूँ लड़सकती हूँ, अधियान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को पार्टी की ओर खींचने में असफल रहा। कांग्रेस 403 सीटों वाली विधानसभा में केवल दो सीटों तक सिमट कर रह गई, जो पार्टी का राज्य में अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। अब प्रियंका यूपी छोड़ चुकी हैं। प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे अभी तक झारखंड के प्रभारी थे। कांग्रेस की दुर्दशा पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यूपी में पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया है क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में अपने बड़े-बड़े चेहरों को खोते गए। जो यहां रुके उन्होंने भी रोज़मर्रा के मसलों से दूरी बनाए रखी, लेकिन यह सब बदलाव तभी सफल हो पायेंगे जब कांग्रेस यूपी में संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ जनता से जुड़ी समस्याओं के लिये मुखरता से आवाज उठाये। मगर ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी को भी माफ नहीं किया जा सकता है। जो पार्टी जनादेलन से खड़ी हुई थी, अब वह सड़क पर लड़ते हुए नहीं दिखाई देती है। अखिलेश यादव अपने बयानों से सुर्खियां तो बटोरते रहते हैं, परंतु मतदाताओं से उनकी दूरी सपा के आगे बढ़ने के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है। सपा की मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत भी सपा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। खासकर जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जिस तरह सपा ने दूरी बनाये रखी, वह सपा के पिछड़े और दलित वोटों को भी रास नहीं आ रहा है क्योंकि राम सभी हिन्दुओं की आस्था से जुड़े हैं। पहले सपा ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई। फिर यूपी विधानसभा में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बधाई संदेश पास किया गया तो यहां भी सपा विगेध में खड़ी नजर आई। अब जबकी

नास किया गया तो वह ना सका ताकि न खड़ा नजर आइ जब जेबों
योगी सरकार ने 11 फरवरी को सभी दलों के विधायकों को रामलला के
दर्शन का कार्यक्रम बनाया तो उससे भी सपा ने किनारा कर लिया। ऐसा
लग रहा है कि सपा को बीजेपी के साथ-साथ रामलला से भी परहेज है।
आज तक अखिलेश अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गये हैं। सपा
के विरोध का स्तर यह है कि उसकी पार्टी के विधायक रामलला के साथ
अयोध्या के धनीपुर में जहाँ मस्जिद बननी है, वहाँ का भी भ्रमण कराये
जाने की बेतुकी मांग करने लगे हैं, जबकि अपी वहाँ काम तक शुरू नहीं
हुआ है। मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत के लिये सपा प्रमुख ने स्वामी
प्रसाद मौर्य की तरफ मुंह मोड़ लिया है, जो लगातार हिन्दू-देवी-देवताओं
के लिए अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं। लब्जोलुआब यह है कि यूपी में
बसपा विहीन इंडी गठबंधन इस समय वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। जो
हालात नजर आ रहे हैं, उससे तय है कि बीजेपी के लिए यूपी में कोई बड़ी
चुनौती नजर नहीं आ रही है। रालोद ने यदि इंडी गठबंधन से दूरी बना ली
तो पश्चिमी यूपी में सपा के लिये बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा। वर्से भी वेस्ट
यूपी में सपा लगभग नेतृत्व विहीन हो गई है।

छोटे चौधरी का बड़ा खेला, इंडी गढ़बंधन की दृष्टिं नाव से कूदने के लिए लगा है रेला

लत से और स्पष्ट वारधारा गठबंधन में सत्ता हां तक आ रही है तो यहां पर्याप्त है कि नाना तय करना चाहिए। इंडी एवं देश इस में कूद नी होड़ जाए। इंडी नीतीश कांगड़ा वही तरफ संतुलन ममता री बना दल भी तो तरह पार्टी भी बदूने के लिए रही है। ल बचे लड़ रहे तर ही रही है चुनाव किसी विपक्ष नानमंत्री नंबोधन श्योकि आगामी ले दम एनडीए विपक्षी प्रदेश के हो गयी है कि बेमेल विचारधारा वाला यह गठबंधन सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए बना था। जहां तक राष्ट्रीय लोक दल की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भाजपा के साथ आना तय हो चुका है। एकाध दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि राष्ट्रीय लोक दल का भाजपा में विलय भी संभव है लेकिन अगर विलय नहीं हुआ तो गठबंधन होना पक्का है। हम आपको याद दिला दें कि भाजपा ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन का प्रयास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी किया था लेकिन तब जयंत चौधरी ने साथ आने से मना कर दिया था। राष्ट्रीय लोक दल 2014 से सभी चुनाव विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़ा है लेकिन इसका उसे कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जरूर समाजवादी पार्टी से गठबंधन का रालोद को फायदा हुआ था साथ ही सपा कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा की सदस्यता भी मिल गयी थी। लेकिन अब छोटे चौधरी के नाम से मशहूर जयंत चौधरी के पाला बदलने की अटकलों से विपक्षी खेमा बेचैन दिख रहा है। क्योंकि बात यह नहीं है कि छोटा दल गठबंधन से बाहर जा रहा है या बड़ा दल, बात यह है कि लंबे समय से गठबंधन में साथ रहा दल अब दूसरे के साथ जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए ऐलान किया था कि रालोद के लिए गठबंधन में सात लोकसभा

A photograph showing a person's right arm and hand raised, palm facing forward. The person is wearing a light-colored shirt. A microphone is positioned in front of the hand, angled upwards. The background is a plain, light-colored wall.

A medium shot of a man with dark hair and a beard, wearing a light grey button-down shirt with a small diamond pattern. He is standing behind a black podium, speaking into a black microphone. His mouth is open as if he is in the middle of a sentence. The background is a plain white wall, and the top right corner shows a dark, out-of-focus object.

मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे तो जयंती चौधरी भी साथ होंगे। हम आपके बता दें कि नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर से पार्टी के एक महाने के ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता मोदी सरकार के जनकाल्पनिक कल्याणकारी कदमों को रेखांकित करने के अलावा चुनाव घोषणापत्र के लिए किसानों और मजदूरों संहित ग्रामीण आबादी से सुझाव मांगेंगे। पार्टी के सदस्यों लोगों से संवाद के दौरान गांवों में गयों और कृषि उपकरणों की पूजा भी करेंगे। देखा जाये तो नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मुजफ्फरनगर का चयन कर बड़े राजनीतिक सदेश भी दिया है। क्योंकि यह क्षेत्र मोदी सरकार वे कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का केंद्र था। हालांकि बाद में केंद्र ने उन कानूनों को वापस ले लिया था लेकिन आदोलन में भाग लेने वाले किसानों की नाराजगी अब तक दूनहीं हुई है। बहरहाल, जहां तब इंडी गठबंधन की बात है तो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ और घटक या उन घटकों के बड़े नेता सत्तारूप एनडीए का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि देश के राजनीतिक मिजाज से सभी वाकिफ हैं। सर्वाधिक इस बात को समझ रहे हैं कि देश की ताजा राजनीतिक स्थिति यहाँ है कि दस साल के शासन वे बाबजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने की बजाए देश-विदेश में और बढ़ी ही है।

यूसीसी पर उत्तराखण्ड ने जो सार्थक पहल की है उससे दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए

आज जबकि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जी-20 देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर चुका है, भारत की अहिंसा एवं योग को दुनिया ने स्वीकारा है, विश्व योग दिवस एवं विश्व अहिंसा दिवस जैसे आयोजनों की संरचना हुई है। उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने समान आचार संहिता (यूसीसी) के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी और इसे विधानसभा में पेश भी कर दिया। अब चार दिनों के विशेष सत्र में इसे आसानी से पारित भी कर दिया जायेगा। इस तरह देश को आजादी मिलने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले गोवा में यह लागू है। आजादी के अमृतकाल में समानता की स्थापना के लिये इससे अपूर्व वातावरण निर्मित होगा। यह उत्तराखण्ड ही नहीं, समूचे भारत की बड़ी जरूरत है। समानता एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदीशिक लोकतात्त्विक मूल्य है। इस मूल्य की प्रतिष्ठापना के लिये समान कानून की अपेक्षा है। यूसीसी देश की राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में रहा है। हालांकि संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसका उल्लेख है। इस लिहाज से राजनीति की सभी धाराएं इस बात पर एकमत रही हैं कि देश में सभी पथों, आस्थाओं से जुड़े लोगों पर एक ही तरह के कानून लागू होने चाहिए। राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति जब-तक कानूनी प्रावधानों के भेदभाव को झेलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। उत्तराखण्ड एवं गोवा के बाद असम और गुजरात जैसे राज्य भी समान आचार सांहाता का लागू करने का तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं नरेन्द्र मोदी सरकार यूसीसी लागू करने की मांग जोरदार तरीके से करती आ रही है और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया है। भारतीय न्यायपालिका की तरफ से भी बार-बार इसे लागू करने की जरूरत बताई जा रही है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि देश में इसे लेकर जागरूकता हाल के दिनों में बढ़ी है। और इसका श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारत के विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मुद्दे पर देश के तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए थे। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है। पिछले कुछ समय से इस पर अच्छी खासी बहस चली है। लिहाजा एक-एक करके अलग-अलग राज्यों में इसे लागू करने और वहां के अनुभव के आधार पर एसेबद्धने का ख्याल गलत नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखण्ड विधानसभा में इसे पेश किए जाने और वहां बहस शुरू होने के बाद इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर रोशनी पड़ेंगी और सभी दुविधाएं, शंकाएं एवं सदेह दूर हो जाएंगे। जो अन्य राज्यों के लिये लागू करने का आधार बनेगी। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्म-निरपेक्ष देश

कहा-कहा विस्मान के हालात भी पैदा हो रहे हैं। सामुदायिक घटनाओं को भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, घटना को देखने का यह नजरिया वास्तव में वर्ग भेद को बढ़ावा देने वाला है। देश का मुस्लिम भी समाज का एक हिस्सा है, जिसे इसी रूप में प्रस्तुत करने की परिपाठी चलन में आ जाए तो भेद करने वाले विचारों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को ऐसे भ्रम में रखने के लिए प्रेरित किया कि वह भी ऐसा ही चिंतन करने लगा, जबकि सच्चाई यह है कि आज के मुसलमान बाहर से नहीं आए, वे भारत के ही हैं। परिस्थितियों के चलते उनके पूर्वज मुसलमान बन गए। वे सभी स्वभाव से आज भी भारतीय हैं और विचार से सनातनी हैं, लेकिन देश के राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ एवं वोट बैंक के चलते मुसलमानों के इस सनातनी भाव को प्रकट करने का अवसर नहीं दे रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनेक विसंगतियां हैं, जैसे शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था। इसके दुरुपयोग के चलते सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाकर जुलाई 2019 में इसे खत्म कर दिया है। तीन तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग समान नागरिक कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज की महिलाएं इस कानून के समर्थन करने के लिए आग आ रहा है।

1985 में शाहबानो के साथ के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजरात भत्ता देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तलाकालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पलटने के लिए संसद में बिल पास कराया था। इस कानून के समर्थकों का मानना है कि अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका प्रबोध पड़ता है समान नागरिक संहित लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा फिर चाहे वे किसी भी धर्म का वर्षों न हो। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेगे और वोटों का ध्वनीकरण नहीं होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। अगर हम यह चिंतन भारतीय भाव से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही दिखाई देगा कि समान नागरिक कानून देश और समाज के बिकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम समाज को गलती सुधारने की पहल करनी चाहिए

सत्ता लाभ और चुनाव में परायज के भय से पाइड इन लागा का राष्ट्रीय आस्तीन का अवमानना करन आया। उस नकरन में लाज हा नहा आता। लाभ, भय आ भान हा जान का परायाम भारत का राष्ट्रीय समाज 75 वर्ष पूर्व मुग्ध सुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञनवापी मस्जिद में हुए सर्वेक्षण से उस दावे की पुष्टि हो गई है कि वह हिन्दू मंदिर पर ही बनाई गई थी। इस सर्वेक्षण को रोकने के लिए मुस्लिम पराया न्यायालय में चरम सीमा तक जाकर तर्क दिए गए। वही बीती 31 जनवरी को बाराणसी की एक न्यायालय ने हिंदू पक्ष को ज्ञनवापी मस्जिद के व्यास जी तलगृह में पूजा का अधिकार दे दिया है। पूर्ण विधि विधान पूजा अर्चना गुरु हो गई है। हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञनवापी परिसर में स्थित एक तलगृह में पूजा का अधिकार मांग रहा था। यह तलगृह मस्जिद परिसर में है। वर्ष 1992 तक व्यास जी तलगृह में पूजा नियमित तौर पर होती थी। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विघ्यान के बाद 1993 से व्यासजी के तलगृह बंद कर दिया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को लेकर मुलायम सिंह यादव ने बैरिकेडिंग लगा दी कि यहां सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े और लड़ाई-झगड़े ना हों। पहले बांस-बल्ली लगाकर टेपेरी तौर पर बैरिकेडिंग की गई और बाद में पक्की तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद यहां पर वार्षिक तौर पर माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। ज्ञनवापी में किए गए सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई, उसके आधार पर कोई भी कह सकता है कि वह मंदिर ही है। मुस्लिम पक्ष को इसका ज्ञान काफी पहले देखा था। इसीलिए उन वस्तुओं को छिपा दिया गया था और ढक दिया गया था जो हिन्दू धर्म के प्रतीक और चिन्ह हैं। सबसे बड़ी बात शिविलिंग का मिलना है। पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि ज्ञनवापी कुएं का निर्माण स्वयं धरावा विशेष ने अपने त्रिशूल से किया था। पौराणिक काल से ही काशी विश्वनाथ कौरिडोर का इलाका अविमुक्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध रहा है। महाभारत में भी काशी विश्वनाथ कौरिडोर के पूरे क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। तर्तमान में स्थित ज्ञनवापी मस्जिद भी अविमुक्त क्षेत्र का ही भाग रहा है। इस क्षेत्र में स्थित ज्ञनवापी मस्जिद को मुक्त कराने के लिए सैकड़ों वर्षों से विश्व भर के हिंदू संघर्ष कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि स्वतंत्रता के बाद कोंपकर काल में हिन्दू धर्मस्थलों को तोड़कर या उन्हीं ढांचों पर खड़ी की गई मस्जिदों को हिंदुओं को सौंपने की नीति बनाती। लेकिन काग्रेस सहित अन्य पार्टियां मुसलमानों की नाराजगी से बचने के लिए हिंदुओं के वैध दावों को तुकराती रहीं। मथुरा और बाराणसी में हिंदुओं के सर्वोच्च आराध्यों के पवित्र मंदिर के बगल में बनी मस्जिद के हिन्दू मंदिर होने की बात पंडित नेहरू से लेकर तमाम नेताओं को ज्ञात थी। लेकिन उन्होंने इस दिशा में सोचने का कासलिए नहीं उठाया क्योंकि वे हिंदुओं की सहनशक्ति को जानते थे। वरना क्या कारण था कि हिंदुओं की विवाह व्यवस्था संबंधी रीति-रिवाजों को तो उलट-पलट दिया गया किंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई।

